(c) if so, whether Government propose to set up an impartial authority to inspect and certify these building complexes; and

(d) when final decision is likely to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) Housing being a State subject, the State Government set up the housing agencies which cater to the large scale housing needs of the people in each State. As per latest information most of the State except Arunachal Pradesh, Mizoram, Daman & Diu, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands have set up their Housing Boards.

(b) No specific complaint has been received.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Plan outlay for Karnataka for Rainfed Agricultural Scheme

3206. SHRI PRABHAKAR B. KORE : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under C.S.S. National Watershed Development project for Rainfed Agricultural scheme, the Central Government has earmarked a plan outlay of Rs. 300 crores for the year 1992-93 for the Karnataka State; and

(b) if so, how much amount has been released so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) Under National Watershed Development Project for Rainfed Areas, an amount of Rs. 1420.00 lakhs has been earmarked for the year 1992-93 for Karnataka. An amount of Rs. 979.394 lakhs has been released so far to the State under the scheme.

सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण

3207. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्त राम जायसवाल :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में प्रतिदिन बढ़ती जा रही गंदगी की रोकथाम हेतु जन-सुविधाओं का निर्माण करने का विचार है;

(ख) क्या इस मामले में सुलभ इंटरनेशनल के साथ बातचीत की जा रही है अथवा क्या सरकार का उक्त संगठन को इस कार्य में शामिल करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो जन-सुविधाओं की प्रस्तावित कुल संख्या और स्थलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित जनसुविधाओं पर कुल कितनी लागत आएगी और इनका निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली छावनी बोर्ड ने बताया है कि उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाएं पहले से मौजूद हैं । दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने यह जानकारी भी दी है कि और सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण इनकी आवश्यकता और स्थान की सुलभता के अनुसार किया जा रहा है ।

(ख) दिल्ली छावनी बोर्ड तथा दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सुलभ इन्टरनेशनल ने इनके नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में पहले से ही काफी सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया है । नई दिल्ली नगर पालिका ने बताया है कि मौजूदा सार्वजनिक